loaded for despatch to customers instead of at the consumers' end. A decision has been taken to progressively shift the sampling to the loading points. To begin with, sampling at loading points has been started from 1-6-92 for despatches to thermal power stations from Eastern Coalfields Ltd., Cental Coalfields Ltd. and Bharat Coking Coal Ltd. under the aegis of Coal Controller.

Shifting of sampling to the loading points is not likely to have any impact on realisation of coal sales dues. However, Coal India Ltd. have introduced the "Cash and Carry" scheme with effect from 1-10-91 under which coal is supplied to thermal power stations against advance payments. This scheme has helped Coal India Ltd. in realising a substantial portion of their coal sales dues against current supplies.

विज्ञापन एजेन्सियों पर बकाया राशि

*330. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन एजेन्सियों ने दूरदर्शन को कुल कितनी धनराशि देनी थी और ऐसी एजेन्सियों के नाम क्या हैं ;

(ख) एक वर्ष से अधिक अवधि की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इतनी लम्बी अवधि तक राशि को वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) विज्ञापन एजेन्सियों के नाम विज्ञापन प्रभारों की 12.12 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। अलग-अलग एजेन्सियों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) विज्ञापन एजेन्सियों से बकाया राशियों की मानीटरिंग करने और उन्हें वसूल करने के लिए दूरदर्शन में एक छोटा कार्य-दल गठित किया गया है।

चलती-फिरती उचित दर दुकानों के लिए वाहन

*331. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चलती-फिरती उचित दर दुकानों के लिए राज्यों को वाहन उपलब्ध कराये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे वाहनों की संख्या क्या है;

(ग) इस बात का पता लगाने के लिए क्या मानदंड निश्चित किए गए हैं कि इन वाहनों से उचित दर पर वस्तुओं का वितरण किन क्षेत्रों में किया जाये ;

(घ) फिलहाल ऐसे वाहनों के माध्यम से वितरण व्यवस्था का संचालन करने वाले अधिकारियों के पद नाम क्या हैं ; और

(ङ) ऐसे स्थानों पर निर्धारित वस्तुओं के उचित वितरण को प्रमाणित करने वाले अधिकारी का पदनाम क्या है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार पर्वतीय, आदिवासी, रेगिस्तानी और दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर दुकानों के रूप में चलाने के लिए वैनों की खरीद हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देती है। वनों की संख्या, जिनके लिए सहायता दी गई है, का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने का काम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जिम्मे है,

अतः उनके प्रचालन के बारे में, जिसमें कर्मचारियों की ड्यूटी हेतु तैनाती करना आदि शामिल है, निर्णय उनके द्वारा किया जाता है ।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1985-86 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान चलती-फिरती उचित दर दुकानों के रूप में चलाने हेतु वैनों की खरीद के लिए दी गई वित्तीय सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वाहनों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	33
2. असम	18
3. बिहार	76
4. हिमाचल प्रदेश	18
5. कर्नाटक	26
6. केरल	9
7. हरियाणा	10
8. जम्मू व कश्मीर	13
9. मध्य प्रदेश	44
10. महाराष्ट्र	24
11. मणिपुर	16
12. मेघालय	6
13. मिजोरम	4
14. नागालैण्ड	11
15. उड़ीसा	48
16. पंजाब	4
17. राजस्थान	61
18. सिक्किम	4
19. तमिलनाडु	11
20. उत्तर प्रदेश	72
21. चंडीगढ़	2
योग	510

Heavy losses Incurred by drug companies in Public Sector

*332. SHRI SURESH KADMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether if is a fact that all the Public Sector companies manufacturing drugs, except one, are in the red and have been incurring heavy losses; and

(b) if so, what are the reasons therefor and what remedial measures have been taken by Government to improve their working?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) There are five public sector drug companies under the Department of Chemicals & Petrochemicals, namely, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., (IDPL), Hindustan Antibiotics Limited (HAL), Bengal' Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL), Bengal Immunity Ltd. (BIL) and Smith Stanistreet Pharmaceuticals Limited (SSPL). Of the five public sector drug units, 4 namely, IDPL, BCPL, BIL and SSPL have been incurred heavy cash as well as net losses over the years.

(b) (i) The major reasons for losses of these units are attributed to obsolescence in technology, high wage component, low productivity, high incidence of interest burden, inadequate marketing set up, constraints of working capital, constraints in rolling of working capital, excess manpower and consequently high fixed cost.

(ii) The package for improvement in the performance of these units would involve stepping up of capacity utilisation, emphasis on higher sales, increase in efficiency by savings on services and utilities, cost reduction, improvement in the system of collection of outstanding dues, implementation of Voluntary Retirement Schemes. This would require sizeable injection of Plan/Non-Plan funds and write-off of accumulated Government loans and interest.

(iii) Most of the above measures could not be implemented, as requisite funds were not available due to resource constraints of the Government.

(iv) Voluntary retirement scheme which is an integral part of Rehabilitation of